

फरीदाबाद

मजदूर समाचार

मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर ' 136

काम कम ।

बातें ज्यादा ।।

डाक पता : मजदूर लाइब्रेरी,
आटोपिन झुग्गी,
एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001

अक्टूबर 1999

माहौल ऐसा ही है इसलिये (2)

ऐसा नहीं है कि जानते नहीं हैं। साफ-साफ दीखता है कि वर्तमान माहौल आबादी के विशाल बहुमत के खिलाफ है।

लेकिन क्या करें? कोई राह, कोई तरीका नजर नहीं आता। अपने को असहाय पाते हैं। मजबूरी मान कर वर्तमान में स्वयं को एडजस्ट करने के प्रयास करते हैं। जानते हुये.....

जानते हुये मक्खी निगलना

..... गलत है। जानते हैं गलत है। जानते हुये गलत करते हैं।

ऐसे में बेहद गिरावट नई सीमायें पार करती हैं। संग-संग, फैलती कुँठायेँ बालपन-शिशुपन को लीलने लगी हैं।

यह है वर्तमान। ऐसा ही है माहौल।

इस माहौल की बुनियाद में, फैक्ट्रियों में

घेरों में बन्द मजदूर। गेटों पर गार्ड। घड़ी की सूइयों की डिक्टेटरशिप। मैनेजरो-सुपरवाइजरो-दल्लों-चमचों के जटिल धारदार-काँटेदार जाल। और, मजबूरी में मजदूर बनते प्रत्येक व्यक्ति को हर समय घेरे रहते छोटे-बड़े ढेरों डर-भय। पहली नजर में लगता है कि फैक्ट्रियों में मजदूर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा कुरेदते ही.....

सागर मन्थन

..... फैक्ट्रियों में मजदूर इतने प्रकार के कदम उठाते हैं, इतने तरीके अपनाते हैं कि हर रोज ही मैनेजमेंटों के फन्दों-जालों में बड़े-बड़े छेद कर देते हैं। इसलिये सरकारों-मैनेजमेंटों की नियती-सी बन गई है कि मजदूरों को जकड़े रखने के लिये भ्रमों-धोखों के पुराने फन्दों-जालों की मरम्मत के संग-संग नये-नये जाल बुनने में लगातार लगी रहें। और, कमजोर पड़ते जा रहे धोखातन्त्र को देखते हुये दमनतन्त्र को मजबूत करें, पुलिस-फौज-गुण्डों की सँख्या व हथियारों में लगातार वृद्धि करें।

मैनेजर-फोरमैन की दादागिरी के जरिये मजदूरों को दबाये रखने को मजदूरों ने बीते जमाने की चीज-सी बना दिया है। मैनेजरों और सुपरवाइजरो की भीड़ खड़ी करनी पड़ी है

पर वे भी मजदूरों ने लकवाग्रस्त-सी कर दी हैं।

लीडर के जरिये मजदूरों के नकेल डालने को भी मजदूरों ने कारगर नहीं रहने दिया है। मैनेजमेंटों को विशाल लीडरी विभाग बनाने पड़े हैं - दल्लों, चमचों, दादाओं, पट्टों के रूप में मजदूरों के बीच से दस-बारह प्रतिशत को छाँट कर टुकड़खोर बनाना पड़ा है ताकि मजदूरों पर जकड़ कायम रख सकें। लेकिन....

सूँघते चमचों के बीच

..... "मैं डरती नहीं हूँ", "मैं मुँह पर बोल देता हूँ" को फालतू की फिंकरेबाजी ही नहीं बल्कि नुकसानदायक जान कर मजदूर तेजी से ऐसी भाषा से पल्लू झाड़ रहे हैं। आजकल मजदूरों के बीच आम चर्चा बन गई है कि लम्बी-चौड़ी हाँकने वाले नादान हैं, बेवकूफ हैं अथवा मैनेजमेंट के, सरकार के पट्टे हैं - हर अवस्था में खतरनाक हैं। दूसरों के लिये कुर्बानी-उर्बानी देने की बातों पर शक-शँका करना सामान्य बात बन गई है। "दूसरों को प्रभावित करो" की वर्तमान की चारित्रिकता दिखावे-दर-दिखावे लिये है - यह बात अब किसी से छिपी नहीं है।

"यह करेंगे", "चन्दा इकट्ठा करो", "मीटिंग में आओ", "उस नेता के पास चलो" जैसी बातें और उन पर अमल मजदूरों ने बहुत कम कर दिये हैं। इस से चमचे तो काफी हद तक नाकारा हो ही रहे हैं, जासूसों से भी मैनेजमेंटें कुछ खास हासिल नहीं कर पा रही।

मैनेजमेंटों के विरोध के लिये लीडरी-भाषा को टुकराते मजदूर आम बोल-चाल की भाषा का अधिकाधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। आम बोल-चाल की भाषा में मजदूर अपनी बातें कह भी रहे हैं पर चमचों-जासूसों की रिपोर्ट किसी को निशाना नहीं बना पा रही। निगाह में नहीं आने, टारगेट नहीं बनने के यह तौर-तरीके दादाओं को भी मात्र खाने-पीने वालों में परिवर्तित कर रहे हैं। इस सिलसिले के बढ़ने पर दादाओं वाला यही हाल पुलिस का, फौज का नाटो फौज का भी, यू एन फौज का भी।

चमचे-कड़छे बीच में बैठे हों चाहे ओट में कान लगाये सुन रहे हों, लीडरी-भाषा की अर्थी उठने के साथ मजदूरों के बीच होती बातचीतें

सम्पूर्णता में ही मैनेजमेंटों के फन्दा कसती हैं। लेकिन आये दिन होती बातें स्वयं में विभिन्न आकार-प्रकार के टुकड़ों में होती हैं और किसी टुकड़े की मैनेजमेंटें कितनी ही चीर-फाड़-जाँच क्योँ न कर लें, उनके हाथ कुछ नहीं आता।

और, मुँह खोले बिना बोलना

आपस में मजदूर पता नहीं क्या-क्या बातें करते हैं पर किसी साहब से वास्ता पड़ता है तब आमतौर पर "हाँ जी", "नाँ जी", "पता नहीं जी" ही मजदूरों का शब्दकोष बन जाता है। वैसे, इक्के-दुक्के वरकर ऐसे भी होते हैं जो बक-बक में साहबों के दिमाग चाट जाते हैं।

गूँगों के मुँह खुलवाने के लिये मैनेजमेंटें आजकल बहुत पापड़ बेल रही हैं। मजदूरों के मुँह खुलवाने के लिये कम्पनियों ने मानव संसाधन विकास विभाग खोले हैं और बक-बक विशेषज्ञों को उनका मुखिया बनाया है। असल में मैनेजमेंटों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि साहबों के सामने मजदूर मुँह नहीं खोलते। मैनेजमेंटों की दिक्कतें तो यह हैं कि बिना मुँह खोले मजदूर हजारों ढँग से बोलते हैं। बन्द मुँह से मजदूरों का यह बोलना मैनेजमेंटों को अन्दर तक चीरने वाली चोटें करता है और सोने में सुहागा यह कि किसी वरकर को पकड़ना भी असम्भव-सा।

हजारों तार होते हैं; हजारों नट-बोल्ट होते हैं; नालियाँ-सीवर होते हैं; कई-कई ऑपरेशन होते हैं; रात-दिन को लपेटे शिफ्टें होती हैं;

और, हर मजदूर के हाथ-पैर-बुद्धि!
"कब कौन मजदूर क्या कर देगी, क्या कर देगा" की अनन्त चिन्ताओं में मैनेजमेंटों को गँजी करना नई फसलें उगाने के लिये, नई समाज रचना की दिशा में कदम है। (जारी)

★ Reflections on Marx's
Critique of Political Economy

★ a ballad against work

★ Self Activity of Wage-Workers:
Towards a Critique of
Representation & Delegation

The books are free

सावधान ! कानून हैं ! !

श्री ललित फैब्रिक्स मजदूर : " साढ़े चार साल से फैक्ट्री बन्द है। हमारे पैसे फँसे हुये हैं। लीडर कह रहे थे कि तीन केस जीत लिये हैं और पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन अब कहते हैं कि बैंकों ने केस कर दिया है। "

रेमिंग्टन वरकर : " हाई कोर्ट में मैनेजमेन्ट ने 28 मजदूर सरप्लस बताये। 28 को कानून अनुसार हिसाब देने और फैक्ट्री चालू करने का फैसला हुआ। लेकिन अब मैनेजमेन्ट बोल रही है कि पैसे नहीं हैं, फैक्ट्री नहीं चला सकती। इस पर अदालत की अवमानना का मुकदमा करने की बात उठी तो बड़े लीडर ने यह केस करने से मना कर दिया। "

कमला सिनटैक्स मजदूर : " हाई कोर्ट में और लेबर कोर्ट में तारीखें पड़ रही हैं। मैनेजमेन्ट कभी कहती है कि कुछ मजदूरों को निकाल कर फैक्ट्री चालू करेगी और कभी कहती है कि मशीनें बेचने दो तो हिसाब देगी। फैक्ट्री में तालाबन्दी नहीं की है पर दो साल से फैक्ट्री में उत्पादन बन्द किया हुआ है। दो महीनों की तनखा और तीन साल का बोनस पहले ही बकाया था। 900 में से फिर भी कुछ मजदूर अभी भी रोज फैक्ट्री में आते हैं। इधर मैनेजमेन्ट ने हमारा फैक्ट्री आना रोकने के लिये पुलिस में तोड़-फोड़ की झूठी एफ. आई. आर. लिखवाई है। "

झालानी टूल्स वरकर : " ढाई साल पहले रिटायर हुआ। सर्विस-ग्रेच्युटी के पैसे के लिये भी केस करना पड़ा। केस जीत गया पर मैनेजमेन्ट ने पैसे नहीं दिये। लेबर अफसर ने मामला डी.सी. के पास भेज दिया। डी.सी. ने फाइल तहसीलदार को भेज दी। तहसीलदार के पास फाइल पहुँचे 9 महीने हो गये हैं। मुझे अभी तक सर्विस-ग्रेच्युटी के पैसे नहीं मिले हैं। केस जीते झालानी टूल्स के 5 और रिटायर वरकरों की सर्विस-ग्रेच्युटी की फाइलें तहसीलदार के पास पड़ी हैं। "

कटलर हैमर मजदूर : " दिक्कत यह है कि हम वरकर शिकायतें कम करते हैं। "

गाँव गया फैक्ट्री मजदूर : " प्रतापगढ़ जिले के एक गाँव में इस साल धान की रोपाई के समय महिला मजदूरों ने बिना किसी को लीडर बनाये, बिना किसी संगठन का पल्लू पकड़े दिहाड़ी बढ़ाने को कहा। खेतों वालों ने दिहाड़ी नहीं बढ़ाने और जो बढ़ायेगा उस पर 1000 रुपये जुर्माना करने का फैसला किया। महिला मजदूरों ने रोपाई नहीं की। खेतों वालों के परिवारों को खुद धान की रोपाई करनी पड़ी और कुछ खेत खाली भी रह गये। तमाम तरह की धमकियाँ महिला मजदूरों को दी जा रही हैं। "

बातें यह भी

सैन्ट्रो फार्मास्युटिकल मजदूर : " प्लाट 99 सैक्टर-6 की मैनेजमेन्ट बिना वरकरों को हिसाब दिये चुपके से फैक्ट्री बेचने की योजना बना रही है। अतः सभी प्रापर्टी डीलरों एवं क्रेताओं को सूचित किया जा रहा है कि हमारी 15-17 वर्ष की सर्विस का हिसाब देना खरीदने वाले की जिम्मेदारी होगी। "

ईस्ट इंडिया कौटन वरकर : " 12 सितम्बर को तालाबन्दी को 3 साल पूरे हो गये। 14 को मैनेजमेन्ट ने पर्चा बाँट कर मजदूरों को डराया, धमकाया और लालच भी दिया। 'श्रमिक स्वयं बात करें' के नाम पर मैनेजमेन्ट ने 17 तारीख को मीटिंग रखी। 2500 में से 50-100 लोग ही पहुँचे - उनमें से कमेटी बना कर मैनेजमेन्ट ने 20 सितम्बर के अखबारों में छपवा दिया कि फैक्ट्री खोलने का समझौता हो गया है। अक्टूबर आ गया है पर फैक्ट्री में तालाबन्दी जारी है। "

फर आटो मजदूर : " घाटा है कह कर मैनेजमेन्ट बोनस नहीं दे रही। जबकि, कानून कहता है कि बोनस तो बकाया वेतन है और कम्पनी को घाटा हो उस वर्ष भी 8 दशमलव 33 प्रतिशत बोनस देना अनिवार्य है। "

भास्कर रिफ्रेक्ट्रीज वरकर : " टाइम पर वेतन कभी नहीं देते। अगस्त की तनखा आज 14 सितम्बर तक नहीं दी है। काम के लिये बहुत जबरदस्ती करते हैं। "

कास्टमास्टर मजदूर : " 5-6 साल से काम कर रहे वरकर कैजुअल हैं। परमानेन्ट के पैसे बेसिक में बहुत कम बढ़ाते हैं, ज्यादातर अलाउन्सों में देते हैं। "

सेवा इन्टरनेशनल वरकर : " मैनेजमेन्ट काम नहीं दे रही। चार महीने के ओवर टाइम काम के पैसे नहीं दे रही। अगस्त की तनखा आज 11 सितम्बर तक नहीं दी है। "

फरीदाबाद फोरजिंग मजदूर : " 16 सितम्बर को मैनेजमेन्ट ने शोर मचाया कि डेढ़ लाख रुपये चोरी हो गये हैं। पियन को सेक्युरिटी से पिटाया। दो घन्टे बाद कहा कि चोरी नहीं हुई थी बल्कि हिसाब में गड़बड़ थी। "

एस.पी.एल. मजदूर : " छुट्टी की होगी जैसे झूठे-मूठे बहाने बना कर ठेकेदार 200-300 रुपये वेतन में से काट लेते हैं। डाइंग मास्टर गलत तरीके से पेश आते हैं और सबसे बड़ा डाइंग मास्टर तो गालियाँ बहुत बकता है। रँग-रोगन से बहुत बुरा हाल रहता है - डाइंग में परमानेन्ट को एक घन्टा लन्च देते हैं पर ठेकेदारों के वरकरों को आधा घन्टा ही देते हैं। "

हिन्दुस्तान सिरिज मजदूर : " कैंटीन नहीं है। कम्पनी चाय भी नहीं देती। आठ घन्टे बिना चाय पीये काम करना पड़ता है, किसी दिन घर से लन्च न लायें तो भूखा रहना पड़ता है। "

अलकॉन इण्डिया वरकर : " हैड का तो

कम्पनियाँ किसी की नहीं होती

एस्कोर्ट्स मजदूर : " टीआईए हैड श्री जे. एस. कुमार 500 मजदूरों के सिर पर बैठे थे। मजदूरों को बिल्कुल निचोड़ डालने के लिये एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट की आई.ई. नोर्म्स योजना लागू करने में कुमार साहब ने जी-तोड़ मेहनत की। लेकिन अब डिविजनल मैनेजर श्री कुमार स्वयं ही कम्पनी के लिये फालतू हो गये हैं। इसलिये 20-25 साल से प्रोडक्शन क्षेत्र में रहे और 500 मजदूरों के सिर पर पहुँचे कुमार साहब को इन्सपेक्शन में ट्रान्सफर कर मात्र 8 मजदूरों के सिर पर बैठाया गया है ताकि अपमानित हो कर नौकरी छोड़ दें। "

" बीस-तीस साल से कम्पनी की वफादारी कर रहे मैनेजरों व सुपरवाइजर्स को थोक में निकालने का सिलसिला एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट ने शुरू कर दिया है। हर प्लान्ट के बड़े साहब बुला कर कह रहे हैं: '..... जी, आपने बहुत साल कम्पनी की सेवा की है। मुझे यह शब्द कहने तो नहीं चाहियें पर कॉरपोरेट से आदेश आया है। कम्पनी को अब आपकी सेवा की जरूरत नहीं है। '"

कहना ही क्या, पूरा स्टाफ बहुत बुरा व्यवहार करता है। ई.एस.आई. के पैसे काटते हैं, कार्ड नहीं देते। फण्ड काटते हैं, पर्ची नहीं देते। रजिस्टर में 1910 पर दस्तखत करवाते हैं पर पैसे 56 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देते हैं। ओवर टाइम जबरन करवाते हैं पर पेमेन्ट तीसरे महीने में जा कर देते हैं। कुछ बोलो तो निकाल देते हैं। हिसाब माँगने पर गालियाँ देते हैं, पैसा एक नहीं देते। फण्ड फार्म भरने से पहले रिजाइन लिखवाते हैं और जिनका 2 साल फण्ड काटा है उनका एक साल का भरते हैं। दो-चार महीनों में जिन्हें निकाल देते हैं उनका तो फण्ड का पूरा पैसा ही खा जाते हैं। "

मजदूर समाचार में साझेदारी के लिये :

★ अपने अनुभव व विचार इसमें छपवा कर चर्चाओं को कुछ और बढ़वाइये। नाम नहीं बताये जाते और अपनी बातें छपवाने के कोई पैसे नहीं लगते।

★ बाँटने के लिये सड़क पर खड़ा होना जरूरी नहीं है। दोस्तों को पढ़वाने के लिये जितनी प्रतियाँ चाहियें उतनी मजदूर लाइब्रेरी से हर महीने 10 तारीख के बाद ले जाइये।

★ बाँटने वाले फ्री में यह करते हैं। सड़क पर मजदूर समाचार लेते समय इच्छा हो तो बेझिझक पैसे दे सकते हैं। रुपये-पैसे की दिक्कत है।

महीने में एक बार ही छाप पाते हैं और 5000 प्रतियाँ ही फ्री बाँट पाते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें।

कैजुअल और ठेकेदारों के मजदूर

बिजली बोर्ड मजदूर : "थर्मल पावर हाउस में हम 500 मजदूर ठेकेदारों के हैं। कई साल से हम लगातार काम कर रहे हैं। तनखा हमें 1200 रुपये महीना देते हैं।"

हर्लपूल वरकर : "ठेकेदार लोग कम्पनी से सरकारी ग्रेड प्लस कमीशन लेते होंगे पर हमें 45 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी ही देते हैं। साप्ताहिक छुट्टी नहीं देते। दो कैन्टीन हैं - एक में परमानेन्ट वरकरों को, सरस्ते में भोजन देते हैं और दूसरी में हमें सिर्फ चाय देते हैं मार्केट रेट पर। लन्च में हमें गेट के बाहर खाने नहीं जाने देते। न तो हमें ई.एस.आई. कार्ड देते हैं और न प्रोविडेंट फण्ड की स्लिप। आठ घन्टे ओवर टाइम काम के भी हमें 45 रुपये ही देते हैं। दिहाड़ियों में गड़बड़ करके ठेकेदार हर महीने दो-तीन दिहाड़ियों के पैसे भी खा जाते हैं। ठेकेदारों की बदमाशियों के खिलाफ हम कम्पनी के परसनल मैनेजर के पास गये और विरोध में

ओसवाल इलेक्ट्रिकल वरकर : "परमानेन्ट 20-25 हैं, ठेकेदारों के 150 के करीब हैं और 250-300 हम कैजुअल हैं। फैक्ट्री में तीन कम्पनियाँ बना रखी हैं जिनमें वर्द्धमान डाइकास्टिंग का तो कहीं नाम तक नहीं है। हमारे नाम 4 महीने एक कम्पनी में, 4 महीने दूसरी कम्पनी में और 4 महीने तीसरी में लिख देते हैं।"

ए.वाई. इन्टरप्राइजेज मजदूर : "मेन्टेनेन्स तथा स्टोर में कम्पनी के हैं और बाकी सब वरकर ठेकेदारों के हैं। हम 150 हैं, किसी को भी ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिया है। ड्युटी 12 घन्टे की है - 75 रुपये देते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। स्टीम की गर्मी में टेबल प्रिन्टिंग करते हैं - 8 घन्टे के 50 रुपये में कितने दिन चल पायेंगे।"

ट्रान्सफॉर्मर इन्डस्ट्रीज वरकर : "हम 150 मजदूर हैं। काम बहुत ज्यादा लेते हैं पर तनखा में 1000-1200-1300-1400 रुपये ही देते

आटोपिन वरकर : "कैजुअलों और ठेकेदारों के मजदूरों को जुलाई की तनखा आज 10 सितम्बर तक नहीं दी है - परमानेन्टों को भी जुलाई के पैसे 7 सितम्बर को जा कर दिये। दिन में दस बार गालियाँ और धमकियाँ देने के लिये मैनेजमेन्ट ने आदमी रखे हैं।"

एस्कोर्ट्स मजदूर : "एक्सीडेंट में एक कैजुअल की आँख पर चोट लगी थी और एक की पँसलियाँ टूट गई थी व कटने से बाल-बाल बचा था। दस साल से वे वरकर कैजुअल ही हैं - बार-बार ब्रेक कर देते हैं।"

स्टार वायर वरकर : "फैक्ट्री के अन्दर कई प्लान्ट हैं और ज्यादातर मजदूर कैजुअल व ठेकेदारों के हैं। 4-5 साल पुराने कैजुअलों को 1350 और 8-10 साल वालों को 1600 रुपये महीना वेतन देते हैं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं, फण्ड की पर्ची नहीं। तनखा हर महीने देर से देते हैं - जुलाई की 25 अगस्त को दी और अगस्त

क्या-क्या नहीं करें और क्या-क्या करें

मजदूरों को आमतौर पर कोई राहत नहीं मिलती : ● श्रम विभाग, पुलिस, प्रशासन, अदालतों और अन्य सरकारी विभागों में जाने पर ; ● यूनियनों और पार्टियों के लीडरों के पास जाने से ; ● दादाओं अथवा प्रतिष्ठित लोगों के पास जाने से।

बल्कि : सरकारी ताम-झाम की भूल-भुलैया, नेताओं के लटकों-झटकों और गुण्डों की फूँ-फाँ के चक्करों में पड़ने पर मजदूरों की परेशानियाँ आमतौर पर बढ़ती ही हैं।

इसलिये जिन कम्पनियों में : ■ रोज 12 घन्टे काम करवाते हैं ; ■ आठ घन्टे ड्युटी और साप्ताहिक छुट्टी के हिसाब से महीने का 2000 रुपये से कम वेतन देते हैं ; ■ 37-40 दिन काम

करने के बाद भी 30 दिन के पैसे नहीं देते ; ■ गालियाँ देते हैं, धमकाते हैं, मार-पीट करते हैं। ऐसी कम्पनियों में मैनेजमेन्टों को बहुत ज्यादा परेशान करके ही मजदूर कुछ राहत हासिल कर सकते हैं। इसके लिये मजदूरों द्वारा बिना किसी प्रकार की झिझक के शान्त मन से, ठन्डे दिमाग से, सोच-विचार कर **ऐसे कदम उठाने चाहिये कि :** ★ पाँच साल दौड़ने वाली मशीनें छह महीनों में टें बोल दें ; ★ कच्चा माल-तेल-बिजली उत्पादन के लिये आवश्यक मात्रा से दुगुनी न सही, डेढी तो इस्तेमाल हो ही ; ★ ऑपरेशन उल्टे-पल्टे हो कर क्वालिटी को गंगा नहा दें ; ★ बिजली कभी कड़के, कभी दमके, कभी आँख-मिचौनी करने मक्का-मदीना चली

जाये ; ★ अरजेन्ट मचा रखी हो तब ऐसे ब्रेक डाउन हों कि साहबों को हृदय रोग हो जायें।

ऐसे कदम बिना शोर-शराबे के, गुपचुप उठाना ही बनता है। मजदूरों की समझदारी ऐसे तरीके अपनाते हैं कि "किया है अथवा हुआ है" की उहापोह में मैनेजमेन्ट का दिमाग खराब हो। इस मासूमियत से कदम उठें कि साहबों को चींटी ढूँढ़ने के लिये हाथी लाने पड़ें।

कैजुअल और ठेकेदारों के वरकरों के लिये यहाँ-वहाँ, इधर-उधर, हर जगह यह सब करना समुद्र में मछली के तैरने के समान आसान है। मैनेजमेन्टों को ज्यादा पगलाने से रोकने हेतु परमानेन्ट मजदूरों के लिये भी यह बहुत सरल तरीके हैं।

नारे भी लगाये। परसनल मैनेजर ने ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया।"

मोहता ब्राइट स्टील मजदूर : "वेतन में 1902 पर हस्ताक्षर करवाते हैं और देते हैं 1500 रुपये।"

गीता इंजिनियरिंग वरकर : "हाजरी रजिस्टर था और वेतन भी रजिस्टर पर देते थे लेकिन अब तो एक छोटी कांपी पर ही यह सब करते हैं। सब काम टेम्परेरी है। ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते।"

मोदी इन्टरनेशनल मजदूर : "हम 300 के करीब वरकर हैं जिनमें से 20-25 ही परमानेन्ट हैं। वेतन 1200, 1500 और 1800 रुपये महीना देते हैं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं, प्रोविडेंट फण्ड नहीं। चार-पाँच साल से काम कर रहे वरकर को जब मर्जी होती है कान पकड़ कर निकाल देते हैं।"

हैं। तीन-चार साल से काम कर रहे हैं। प्रोविडेंट फण्ड नहीं और किसी को ई.एस.आई. कार्ड नहीं।"

सुपर फाइबर लिमिटेड मजदूर : "10 घन्टे की ड्युटी है। कैजुअलों को महीने के 1200 रुपये ही देते हैं। ठेकेदार लोग चार वरकरों को बात करते देख लेते हैं तो गालियाँ और धमकियाँ देते हैं।"

रोलाटेनर्स वरकर : "कैजुअल वरकरों को मैनेजमेन्ट साप्ताहिक छुट्टी नहीं देती।"

इम्पीरियल आटो मजदूर : "ठेकेदार हमें 1500 रुपये महीना वेतन देते हैं। हफ्ते में एक दिन की छुट्टी भी नहीं देते।"

शक्ति इंजिनियरिंग मजदूर : "12 घन्टे की ड्युटी है। महीने भर रोज 12 घन्टे काम करने पर 1800 रुपये तनखा। पैसे 15-20 तारीख को जा कर देते हैं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं, फण्ड नहीं।"

की आज 10 सितम्बर तक नहीं दी है।"

प्रिसिजन इन्डस्ट्रीज मजदूर : "12 घन्टे की ड्युटी है और तनखा 1100 से 1400 रुपये महीना देते हैं।"

इण्डियन हार्डवेयर इन्डस्ट्रीज वरकर : "तनखा 1200 रुपये महीना देते हैं। मैनेजमेन्ट इतनी तिकड़बाज है कि जहाँ कोई जॉच-पड़ताल की बात आई रिश्वत खिला देती है। प्रशासन से मिल कर ही यह सब हो रहा है। ज्यादा दिक्कत तो अपने जैसों से है जो थोड़े से फायदे के लिये चमचागिरी करते हैं।"

इण्डियन गैस मजदूर : "80 में से 40 कैजुअल हैं। वेतन 1400 रुपये तक भी देते हैं।"

सफेदी ठेकेदार : "यह सब कहने की बात है कि कोई गरीबों का भला करता है। बल्कि उल्टा है। मजदूर गरीबों से ही सब की रोटी चलती है, कमाई होती है। लीडरी और ठेकेदारी झूठ बोले बगैर नहीं चलती।"

मामला गम्भीर है

लार्सन एण्ड टूब्रो मजदूर : "एग्रीमेन्ट तो हो गया है पर काम ही नहीं है। मैनेजमेन्ट कहती है कि चिन्ता मत करो। लेकिन मैनेजमेन्ट जब ऐसा कहती है तब चिन्ता तों हमें करनी ही चाहिये। बम्बई प्लान्ट में भी काम नहीं है और वहाँ वरकर निकालने के लिये मैनेजमेन्ट ने वी आर एस लगा दी है।"

सुलजर हाइड्रो वरकर : "पृथला में नया प्लान्ट शुरू हो गया है और ज्यादातर स्टाफ को वहाँ ट्रांसफर कर दिया है। इधर काम नहीं देते और हम फैक्ट्री में 8 घन्टे खाली बैठ कर चले आते हैं। नौकरी से निकालने के लिये वी आर एस लगाई है। हमें भड़काने के लिये मैनेजमेन्ट ने दूर ट्रांसफर कर 7 मजदूरों को 2 महीनों से बाहर निकाला हुआ है।"

एस्कोर्ट्स मजदूर : "दाल में काला है - लीडर कुर्सीत्यागी बन गये। समय से 6 महीने पहले चुनाव करवाया और प्रधान व अन्य धुरन्धर स्वयं खड़े ही नहीं हुये। हारने के डर से खड़ा नहीं होने वाली बात नहीं है क्योंकि ऐसा होता तो वे 6 महीने तो अभी कुर्सियों पर जमे रहते ही और बाद में भी चुनाव टालने की तिकड़में करते। लीडरों की कुर्सी छोड़ने की आतुरता ने नहीं बल्कि मैनेजमेन्ट की जरूरतों ने यह समय-पूर्व चुनाव करवाये हैं।"

"चुनाव में वरकरों की दिलचस्पी खाक होगी। जो खड़े थे उनकी ही रुचि थी। वे पैसे खर्च कर रहे थे क्योंकि उन्होंने पैसे बनाने हैं।"

"बीरम सिंह के जाने से क्या होता है? हमारे गले में फन्दा तो यह आई.ई. नोर्म्स वाली एग्रीमेन्ट है। इतने लोग खड़े हुये थे पर एग्रीमेन्ट के बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं की। असल में चुनाव में मुद्दे तो कोई थे ही नहीं।"

"अभी मैनेजमेन्ट ने मैनेजरों और सुपरवाइजरों को धार पर धरा हुआ है। मैनेजमेन्ट दिवाली के बाद मजदूरों पर धावा बोलेगी। फिर वी आर एस लगायेगी। फार्मट्रैक में 2300 परमानेन्ट वरकर थे, अब 2000 के करीब हैं और मैनेजमेन्ट की चलेगी तो यहाँ मात्र 700-800 ही रहेंगे।"

"एग्रीमेन्ट करके लीडर इतने बदनाम हो गये कि मैनेजमेन्ट उनके जरिये अभी आगे कुछ नहीं कर सकती थी। जबकि, अभी तो मुश्किल से भारी वर्क लोड ही थोप पाई है और भारी संख्या में मजदूरों को निकालना बाकि है। हड़ताल-वड़ताल करवा कर ही मैनेजमेन्ट इतने ज्यादा मजदूर निकाल पायेगी। इसलिये यह समय-पूर्व चुनाव। लगता है कि अब पैसे पर पैसे ले कर मैनेजमेन्ट हमें भड़काने में जुटेगी। अन्याय, अत्याचार, इज्जत का सवाल, ईमानदारी, कुर्बानी, लोकतन्त्र आदि-आदि के चक्कर में पड़ कर हम गर्म हुये और भड़के तो मारे जायेंगे। ठन्डे, शान्त रह कर हम मैनेजमेन्ट की छँटनी योजना को ब्रॉ फेल कर ही सकते हैं, जो वर्क लोड थोपा है उसे भी कम कर सकते हैं।"

हैदराबाद इन्डस्ट्रीज वरकर : "एस्बेसटोस का काम है इसलिये कम्पनी में बीमार मजदूर बहुत हैं। मैनेजमेन्ट के सामने बीमार मजदूरों को निकालना एक बड़ी समस्या है। राजी से तो कोई जायेगा नहीं इसलिये वी आर एस के जरिये उन्हें निकालने के लिये 'इतना पैसा-इतनी किस्ते' की उठा-पटक का ड्रामा चल रहा है।"

बाटा मजदूर : "24 फरवरी को एक दिन की हड़ताल और 25 फरवरी से तालाबन्दी। आठवें महीने में पहुँच गई है फैक्ट्री की तालाबन्दी। वर्क लोड में भारी वृद्धि और मजदूरों की छँटनी के लिये मैनेजमेन्ट यह कसरत कर रही है।"

झालानी टूल्स वरकर : "21 महीनों की तनखा तो पहले ही बकाया थी, इधर दो महीनों की तनखा और बकाया हो गई है। जुलाई का वेतन मैनेजमेन्ट ने 25 सितम्बर तक नहीं दिया था। हालात यह हो गई हैं कि 18 सितम्बर को स्टेटिंग डिपार्ट के वरकर रामस्वरूप की फैक्ट्री में काम करते समय अचानक मृत्यु हो गई। महीने-भर पहले फाइन ग्राइन्डिंग के रामजीत फैक्ट्री में काम करते-करते गिर गये, उनकी मृत्यु हो गई।"

अहिंसक समाज रचना

सत्ता यानि दूसरों के जीवन से सम्बन्धित निर्णय लेना, यानि शासन। चाहे दिल्ली का हो, गाँव का हो या लन्दन का, आखिर गुलामी है।

पार्टियों का उद्देश्य है सत्ता प्राप्त करना। पार्टियाँ मनुष्य के मूल तत्व के विपरीत हैं, इसी कारण समस्यायें हैं।

तन्त्र यानि शासन-प्रशासन। दूसरे, चाहे जन प्रतिनिधि हों, हमारे जीवन के बारे में निर्णय लेते हैं तो वह शासन होता है। शासन में नियन्त्रण-निर्देशन, शासन में आदेश, शासन में कानून-नियम-दण्ड होते हैं। यानि, शासन गुलामी है और गुलामी में दुख-चिन्ता-पीड़ा होगी ही। पराधीन सपनेहु सुख नाहि।

— मदन मोहन ("अपना राज आन्दोलन" की प्रेस विज्ञप्ति से। अजन्ता रोड़, रतलाम - 457001)

अनुभव-दर-अनुभव

टी.टी. आई. मजदूर : "शिक्षा नीति, धर्म नीति, समाज नीति, आर्थिक नीति - जितनी नीति हैं, अब सारी नीति फँस गई हैं। अगर हम मजदूर फँसे हैं तो फँसे नीति बनाने वाले भी हैं।"

भोगल शूज वरकर : "आज माहौल ऐसा हो गया है कि जो नौकरी में हैं वे भी और जो बेरोजगार हैं वे भी घुट रहे हैं। आज के हालात से कौन अवगत नहीं है? सब जानते हैं कि कितने कैजुअल, कितने ठेकेदारों के और कितने परमानेन्ट मजदूर हैं। पूरा तन्त्र अपने निजी स्वार्थ में जुटा है। इसका असर हम पर भी पड़ा है और हम मजदूर भी एक-दूसरे का दुख-दर्द समझने की बजाय स्वार्थी हो कर अपने दुख-दर्दों को और बढ़ा रहे हैं। नेता तो अब बिल्कुल नंगे हैं, चाहे वे कहीं के हों।"

ओरियन्ट फैन मजदूर : "इस कम्पनी में ज्यादा दिन काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बताने में भी तकलीफ होती है कि कितना वेतन मिलता है। 15-20 साल से काम कर रहों को 1800-2000 रुपये देते हैं। ऑफ सीजन में तो इसकी भी कोई गारन्टी नहीं। बिल्कुल ठेकेदारी है - परमानेन्टों को भी पीस रेट है। हमारे में से लोगों को तोड़ कर ही कम्पनी जिन्दा है - 50 चमचे बना रखे हैं। अच्छी बात तो यह है कि कोई यूनियन नहीं है - इसी वजह से नौकरी है।"

एमको प्रेसमास्टर वरकर : "यूनियन है। ग्राइन्डिंग मशीन पर काम करते एक मजदूर ने गुड़ मँगा। मैनेजमेन्ट द्वारा मना करने पर उसने मशीन चलानी बन्द कर दी। इस पर मैनेजर द्वारा गाली-गलौज और उस पर मैनेजमेन्ट की पिटाई। अब एक महीने से सब परमानेन्ट मजदूर बाहर हैं, बस तारीखें चल रही हैं। भड़का कर हमें फँसा दिया है।"

इम्पीरियल आटो मजदूर : "साढ़े तीन-चार घन्टे डेली जबरन ओवर टाइम करवाते हैं। ओवर टाइम पेमेन्ट सिर्फ बेसिक पर देते हैं और वह भी सिंगल रेट से। इससे होता यह है कि ड्युटी के दौरान 8 रुपये घन्टा पड़ते हैं जबकि ओवर टाइम में 6 रुपये घन्टा पड़ते हैं। कोई वरकर ओवर टाइम करने से मना करता है तो उसकी ड्युटी शाम छह से रात ढाई बजे तक कर देते हैं। बिना कोई लैटर दिये 25 सैक्टर के प्लान्ट में ट्रांसफर भी कर देते हैं।"

ड्युरेबल इलेक्ट्रोनिक्स वरकर : "इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का प्लान्ट है और उसके साथ ही इसमें ताला लगा। लेकिन इधर एक दीवार लगा कर काम हो रहा है। कोई बोर्ड नहीं, कोई नाम नहीं। तनखा 200, 500 करके देते हैं।"

खण्डेलवाल प्रा. लि. वरकर : "मजदूरों को गालियाँ बहुत देते हैं और पिटाई भी कर देते हैं। रोज 12 घन्टे की ड्युटी है और उसके बाद भी रोक लेते हैं। फैक्ट्री में हाथ बहुत कटते हैं - साल में 4-5 के तो कंट ही जाते हैं। तनखा 1200-1300 रुपये महीना ही देते हैं।"

विद्यार्थी : "मैं मजदूर समाचार पढ़ता हूँ। सोचता हूँ कि अब हम कौन सी पढाई करें? सब कुछ तो अभी से बेकार ही लगता है।"